



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

PUBLISHED BY AUTHORITY
प्राधिकार से प्रकाशित

312] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 13, 1993/भाद्र 22, 1915

No. 312] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 13, 1993/BHADRA 22, 1915

जल भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 1993

सा.का.नि. 606(अ):—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की धारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 123 के तहत विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट के न्यासी मंडल

द्वारा निर्मित एवं दिनांक 8-1-1993 और 15-1-1993 के आंध्र प्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना में सलग्न अनुसूची के अनुसार विधिवत् रूप से प्रकाशित दीर्घकालीन पट्टा प्रपत्र में संशोधन करने का अनुमोदन करती है।

[फाईल सं. पीटी-17011/7/92-91]

अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

अनुसूची

विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट

दीर्घकालीन पट्टा विलेख की भूमि पट्टा प्रपत्र में संशोधन

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38वाँ) की धारा 123(ख) को महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 के साथ पठित धारा के तहत विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट का न्यासी मंडल आंध्र प्रदेश के राजपत्र दिनांक 19 फरवरी, 1976 में प्रकाशित तथा केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित—देखें उनका पत्र क्रमांक सं. पीटी आई-67/76, दिनांक 22 जनवरी, 1976—दीर्घकालीन पट्टा विलेख में निम्नलिखित संशोधन करना है।

संशोधन

(1) पट्टा विलेख प्रपत्र के पृष्ठ सं. 5 की 6वीं पंक्ति में निम्नलिखित वाक्य जोड़ा जाय: “जिला राजस्व प्राधिकारी द्वारा किये गये मूल्यांकन पर कोई आपत्ति नहीं की जायगी और उसमें किये गये न्यून नियतन का पालन करना होगा तथा इस खण्ड के तहत बनाय गये नियतन और मूल्यांकन अंतिम होंगे”।

(2) पन्नि-7 में कन्वेनट न. 2 में "बिल्डिंग" शब्द के बाद और सेवा प्रभार न्यूनतम देय होंगे।

(3) दोषकालीन पट्टा विलेख के सामान्य प्रावधानों के नवीकरण उप खण्ड ग. 5 को हटा दिया जाय और बाकी खण्डों को पुन नमर दिया जाये।

(4) पट्टा विलेख के सामान्य प्रावधान-7 में व्यवस्थित वर्तमान निर्णयन खण्ड के लिये निम्नलिखित निर्णयन खण्ड रखे।

(1) पट्टा विलेख में जब तक कोई अन्य प्रावधान न हो और जन परिमर (अनधिकृत अग्रिप्राप्ति का निष्कासन) अधिनियम, 1971 या उस समय लागू अन्य किसी नियम द्वारा शासित पट्टा परिमर के निष्कासन में सबंधी मामलों को छोड़कर और पट्टा विलेख के अर्थ में संबंधित सभी विवाद, शकाये, दावे, अधिकार या पट्टा विलेख में संबंधित आदेश और उसमें उत्पन्न किसी स्थिति का जो पट्टा प्रदाता अधि में उत्पन्न हुई हो, उसे निर्णय के लिये केवल अध्यक्ष को ही भेजा जाये। अध्यक्ष का ओर से निर्णय के लिये अध्यक्ष द्वारा ही नियुक्त किसी गैरमंडलाय व्यक्ति को भेज दिया जाये। इस पट्टा विलेख की यह भी एक शर्त है कि उपर्युक्त कथनानुसार विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त व्यक्ति का छोड़कर अन्य कोई भी व्यक्ति निर्णय कार्य नहीं कर सकता। यदि किसी कारणवश यह संभव नहीं होता तो मामला निर्णय के लिये न भेजा जाये। और पट्टादार किसी भी अशालत में इस विषय को नहीं उठायेगा। निर्णय सबंधी विवाद को उठाने वालों वह कोई भी अशालत क्यों न हो पार्टी की सहमति से निर्णयक समय-समय पर पट्टा देने सबंधी प्रकाशन की अधि बढ़ा सकता है।

(2) उक्त के लिये इस प्रकार नियुक्त मात्र निर्णयक मशवार वाली और/अथवा शब्द के प्रत्येक मद के लिये कारण विस्तार रूप में देगा आगे मात्र निर्णयक के

व्याज भुगतान मन्थी/मन्त्रावली अथवा किसी भी रकम—अर्थात् विनिश्चित या पट्टेदार को भविष्य में देय मन्थी के भुगतान का आदेश देना निषिद्ध है।

(3) उपर्युक्त यथा कथन में निर्णायक अधिनियम 1940 के प्रावधान अथवा किसी भी विधायी सभाधन अथवा उनके पुनः-अधिनियमन और उसके अधीन बनाये गये नियम तथा उस समय के त्रिजे लागू नियम इस खण्ड के तहत निर्णय प्रक्रिया पर लागू होंगे।

(4) इस प्रकार के मामले पर संबंधित प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा, पट्टेदार अथवा विभाग पर प्रबंधन तथा निर्णयन के बारे में किसी भी निर्णायक के सामने कोई आपत्ति नहीं करेगा एवं इस प्रकार का निर्णय किसी निर्णय का विरोध मानता नहीं होगा।

नोट —पट्टा विदेश सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है, देखें मन्थन को पत्र में पी टी आर्द-67/76, दिनांक 22 जनवरी, 1976 और आ प्र राजपत्र में 7 दिनांक 19 फरवरी, 1976।

एम पी आर रेड्डी, सचिव

विशाखापट्टणम पोर्ट ट्रस्ट विशाखापट्टणम

विशाखापट्टणम,

1 जनवरी, 1993

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th September, 1993

G S R. 606(Γ).—In exercise of the powers conferred by Sub section (1) of Section 124 of the Major Port Trust Act, 1963, the Central Government

hereby approves the amendment in proforma of long term lease agreement made by the Board of Trustees of Visakhapatnam Port under Section 123 of the Major Port Trust Act, 1963 and duly published in Andhra Pradesh Gazette dated 8-1-1993 and 15-1-1993 respectively as detailed in the Schedule annexed to this Notification.

[File No. PT-17011/92-PT]

ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

SCHEDULE

VISAKHAPATNAM PORT TRUST

AMENDMENT TO LEASE OF LANDS PROFORMA OF LONG TERM LEASE AGREEMENT

In exercise of the powers conferred under section 123(b) of Major Port Trusts Act, 1963 (Act 38 of 1963) read with section 124 of Major Port Trusts Act, 1963 the Board of Trustees of the Port of Visakhapatnam hereby makes the following amendments to the long term lease deed approved by the Central Government vide letter No. PTI-67/76 dated 22nd January, 1976 and published in Part-II of Andhra Pradesh Gazette No. 7, dated 19th February 1976.

AMENDMENTS

(1) In line 6 of page-5 of the Proforma of the lease agreement, the following sentence is to be added "the lessee shall not question the valuation made by the District Revenue Authority and shall abide by the fixation made by lessor therein and the valuation and fixation made under this clause shall be final".

(2) In covenant No. 2 in line-7 after the word 'buildings' the following words may be inserted "and service charges payable to the lessor".

(3) The renewal clause No. 5 of general provisions of the long term lease deed shall be deleted and to renumber the remaining clauses.

(4) Substitute the following arbitration clause for the existing arbitration clause covered by general provision-7 of the lease deed.

(1) Except where otherwise provided in the lease deed and except in the matter relating to eviction of the leased premises which will be governed by the Public Premises (Eviction of unauthorised occupants) Act, 1971 or any other law that may be in force all questions and disputes relating to the meaning of the lease deed as to any other questions of claim, right, matter or thing whatsoever in any way arising out of, relating to the lease deed, orders on these condition¹ arising during the currency of the lease shall be referred to the sole arbitration of the Chairman or a person, not being an employee of the Board, appointed by him to act as sole arbitrate on his behalf. It is also a term of this lease deed that no person other than the person appointed by Chairman of the Visakhapatnam Port Trust as aforesaid should act as arbitrator and, if for any reason, that is not possible the matter is not to be referred to arbitration at all and the lessee shall not question the same in any Court of Law whatsoever regarding referring of dispute to the arbitration. The arbitrator, may, with the consent of the parties, enlarge from time to time, the time for making and publishing the award.

(2) The sole arbitrator so appointed shall give an itemwise speaking and/or reasoned award in detail in respect of each item of claim. Further, the sole arbitrator is prohibited from making an order in the award relating to the payment of interest/compensation or of any other description on any amount i.e. either belated or future payable to the lessee.

(3) Subject as aforesaid the provisions of the Arbitration Act, 1940 or any statutory modification or re-enactment thereof and the Rules made thereunder and for the time being in force shall apply to the arbitration proceedings under this clause.

(4) The decision of the concerned authorities on such issue shall be final, binding and conclusive on the lessee and the Department and shall not be called in question before any arbitrator and such a decision shall not be subject matter of any arbitration.

Note :—The lease deed has been approved by the Government vide Ministry's letter No. PT1-67/76, dated 22nd January, 1976, and published in A.P. Gazette No. 7, dated 19th February, 1976.

Visakhapatnam

1st January, 1993.

M. P. R. REDDY, Secretary,
Visakhapatnam Port Trust Visakhapatnam.

